AMAR UJALA
13.09.2015

विश्वविद्यालयों में ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए जुटे कुलपति व शिक्षाविद

दाखिले से रिजल्ट तक सब कुछ होगा ऑनलाइन

अमर उजाला ब्यूरो

सूबे के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का केंद्रीयकृत डाटाबेस होगा तैयार

यूपीडेस्को ने प्रजेंटेशन के जरिये कुलपतियों को दिखाया योजना का प्रारूप

मुईनुद्दीन चिश्ती वि वि में आयोजित वीसी सम्मेलन में बोलते आशीष श्रीवास्तव व सम्मेलन में मौजूद कुलपति।

लखनऊ। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का केंद्रीयकृत डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे महज एक क्लिक पर इन विश्वविद्यालयों के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। यह सब ई-गवर्नेंस के जरिये संभव हो सकेगा। शनिवार को इसके लिए राजधानी के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय में प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से 15 से अधिक कुलपति व शिक्षाविद जुटे। राज्यपाल राम नाईक के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में यूपीडेस्को के प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन के जरिये ई-गवर्नेंस योजना का प्रारूप दिखाया। गौरतलब है कि राजभवन ने गत 25 जून को सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर सुदृढ़ व पारदर्शी ई-गवर्नेंस प्रणाली अपनाने की बात कही थी।

व्यवस्था पर नियंत्रण होगा आसान, आएगी पारदर्शिता : यूपीडेस्को के प्रतिनिधि आशीष श्रीवास्तव ने कुलपतियों को बताया कि ई-गवर्नेंस से उनके लिए व्यवस्था पर नियंत्रण काफी आसान हो जाएगा। डिग्री और मार्क्सशीट का ऑनलाइन सत्यापन हो सकेगा। प्रवेश व परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया भी तेज होगी। विश्वविद्यालय को यूपी, सीबीएसई और सीआईएससीई के रिजल्ट डाटाबेस से जोड़ दिया जाएगा जिससे किसी अभ्यर्थी का प्रवेश से पहले सत्यापन आसान हो जाए। इससे जहां पारदर्शिता आएगी, वहीं कागज का इस्तेमाल भी कम होगा।

स्टूडेंट्स को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर : इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद छात्र-छात्राओं को माइग्रेशन, प्रॉविजनल डिग्री, डुप्लीकेट मार्क्सशीट, स्क्रूटनी, आरटीआई के तहत स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को देखने जैसे कामों के लिए विश्वविद्यालय नहीं आना होगा। ये कहीं से भी ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, फैकल्टी और स्टूडेंट्स को यूनिक आईडी दी जाएगी। इसके अलावा छात्र कोई शिकायत दर्ज करने के बाद उस पर हुई कार्यवाही के बारे में भी जान सकेंगे।

कुलपति बोले, शासन दे आर्थिक सहायता : ई-गवर्नेंस को लेकर कुलपतियों ने जहां सुझाव दिए, वहीं इसे लागू करने में आने वाली दिक्कतें भी बताईं। लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति प्रो. निरुपमा अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए इस व्यवस्था को अपनाने में कठिनाई की आशंका जताई। पं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के कुलपति प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि इसे लागू करने के लिए शासन को वित्तीय सहायता देनी होगी। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. एसी मिश्रा ने कहा कि निःशक्त छात्र-छात्राएं भी इस पोर्टल का आसानी से उपयोग कर सकें, इस पर ध्यान दिया जाए।

कार्यक्रम में ये हुए शामिल : कार्यक्रम में संयोजक व उर्दू-अरबी-फारसी विवि के प्रो. माहरुख मिर्जा, कुलपति प्रो. खान मसूद अहमद के अलावा फैजाबाद विवि के प्रो. जीसीआर जायसवाल, डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विवि से प्रो. गुरदीप सिंह, फैजाबाद के नरेंद्र देव कृषि व तकनीकी विवि से प्रो. अख्तर हसीब, भातखंडे विवि से प्रो. कुमकुम धर के साथ ही राजभवन के ओएसडी राजवीर सिंह राठौर, वित्त नियंत्रक संजय श्रीवास्तव, आईटी सेल प्रमुख सुदीप बैनर्जी और यूपीडेस्को के वरिष्ठ प्रबंधक एचसी गुप्ता भी शामिल हुए।

कानपुर विवि के कुलपति प्रो. जेवी वैशंपायन, बरेली विवि के प्रो. मोहम्मद मुजम्मिल, झांसी विवि से प्रो. एसी पांडेय, जौनपुर विवि से प्रो. पीआर अग्रवाल, कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि व तकनीकी विवि से डॉ. एसएल गोस्वामी, मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि व तकनीकी विवि से प्रो. एचएस गौड़ और सिद्धार्थनगर विवि से प्रो. आरके पांडेय ने भी शिरकत की।

राजभवन ने इन्हें ऑनलाइन करने का दिया सुझाव

- प्रवेश व पंजीकरण।
- संबद्धता संबंधी प्रकरण।
- मान्यता प्राप्त व संबद्ध महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम, सीट संख्या और फीस का विवरण।
- छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति योजना के तहत पंजीकृत छात्रों और शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण।
- छात्र फीड बैक, सेवायोजन फीड बैक, सतत मूल्यांकन, सत्रांत मूल्यांकन
- मार्क्सशीट, प्रॉविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री, डिग्री सत्यापन आदि।
- छात्र क्रिया-कलाप, ट्रेनिंग व प्लेसमेंट, सतत प्रशिक्षण, पुस्तकालय सुविधा, ई-कंटेंट, वर्चुअल शिक्षण-प्रशिक्षण आदि।